

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 4, बुधवार, शाके 1944-मई 25, 2022 Jyaistha 4, Wednesday, Saka 1944- May 25, 2022	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, मई 25, 2022

संख्या एफ.15(14)पंरावि/विधि/पुनर्गठन/2022/619 :- राजस्थान पंचायती राज अधि नियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते अधि नियम, 1994 की धारा-10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर, भरतपुर को पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के पश्चात तैयार किये गये प्रस्तावों को राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

**आज्ञा से,
नवीन जैन,
शासन सचिव**

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, मई 25, 2022

संख्या एफ.15(14)पंरावि/विधि/पुनर्गठन/2022/620 :- राजस्थान पंचायती राज अधि नियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते अधि नियम, 1994 की धारा-10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर, दौसा को पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के पश्चात तैयार किये गये प्रस्तावों को राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

**आज्ञा से,
नवीन जैन,
शासन सचिव।**

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**(पंचायती राज)****अधिसूचना****जयपुर, मई 25, 2022**

संख्या एफ.15(14)पंरावि/विधि/पुनर्गठन/2022/621 :- राजस्थान पंचायती राज अधि नियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या -13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते अधि नियम, 1994 की धारा-10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर, अलवर को पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के पश्चात तैयार किये गये प्रस्तावों को राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

**आज्ञा से,
नवीन जैन,
शासन सचिव।**

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।